



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 वैशाख 1937 (श0)  
(सं0 पटना 579) पटना, सोमवार, 18 मई 2015

---

विधि विभाग

-----

अधिसूचनाएं

18 मई 2015

एस0ओ0 78, दिनांक 18 मई 2015—बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उपधारा-(1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, वर्ष 1974) की धारा-11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्प्रति जहानाबाद जिला एवं सत्र खंड के अन्तर्गत, अरवल जिला की राजस्व सीमाओं के भीतर उद्भूत दीवानी एवं फौजदारी मामलों, जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो तथा केवल अनन्य रूप से किसी दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय हो, के विचारण एवं निष्पादन हेतु तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में, बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि:-

- (क) अरवल जिला में अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के 2 (दो) न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के 3 (तीन) न्यायालय तथा मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के 1 (एक) न्यायालय स्थापित किये जायेंगे;

- (ख) अरवल जिला के अवर न्यायाधीश के 2 (दो) न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के 3 (तीन) न्यायालय तथा मुंसिफ के 1 (एक) न्यायालय की अधिकारिता अरवल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा होगी;
- (ग) अरवल जिला के उक्त छह (6) न्यायालय अरवल में बैठेंगे तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के नियंत्रण एवं अधिकारिता में रहेंगे।
- (घ) यह अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2015 से प्रभावी होगी।

(सं०सं० ए/एक्ट-8/2001/3218/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

18 मई 2015

एस०ओ० 79, एस०ओ० 78, दिनांक 18 मई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं० ए/एक्ट-8/2001/3218/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

*The 18th May 2015*

S.O. 78, dated the 18th May 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and sub-section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and sub-section(1) of Section 11 of The Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and in modification of the previous notifications and orders issued on the subject, the Governor of Bihar is pleased to direct that for trial and disposal of the Civil and the Criminal cases not triable by Court of Sessions and exclusively triable only by any Magistrate arising within the revenue limits of Arwal District, presently under the Jehanabad District and Sessions Division:-

- (a) 2 (two) Courts of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)], 3 (three) Courts of Judicial Magistrate, First class/Second class [Civil Judge (Junior Division)] and 1 (one) Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] shall be established at Arwal District;

- (b) The Jurisdiction of 2 (two) Courts of Subordinate Judge, 3 (three) Courts of Judicial Magistrate, First class/Second class and 1 (one) Court of Munsif of Arwal District shall be the entire revenue limits of the Arwal District;
- (c) The above mentioned 6 (six) Courts of Arwal district shall hold their sittings at Arwal and remain under the control and jurisdiction of District and Sessions Judge Jehanabad.
- (d) This Notification shall come into force with effect from dated the 20th May, 2015.

**(F.No. A/Act-8/2001/3218/J.)**

By order of the Governor of Bihar,

**AKHILESH KUMAR JAIN,**

Secretary to the Government.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 579-571+100-डी0टी0पी0।

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**